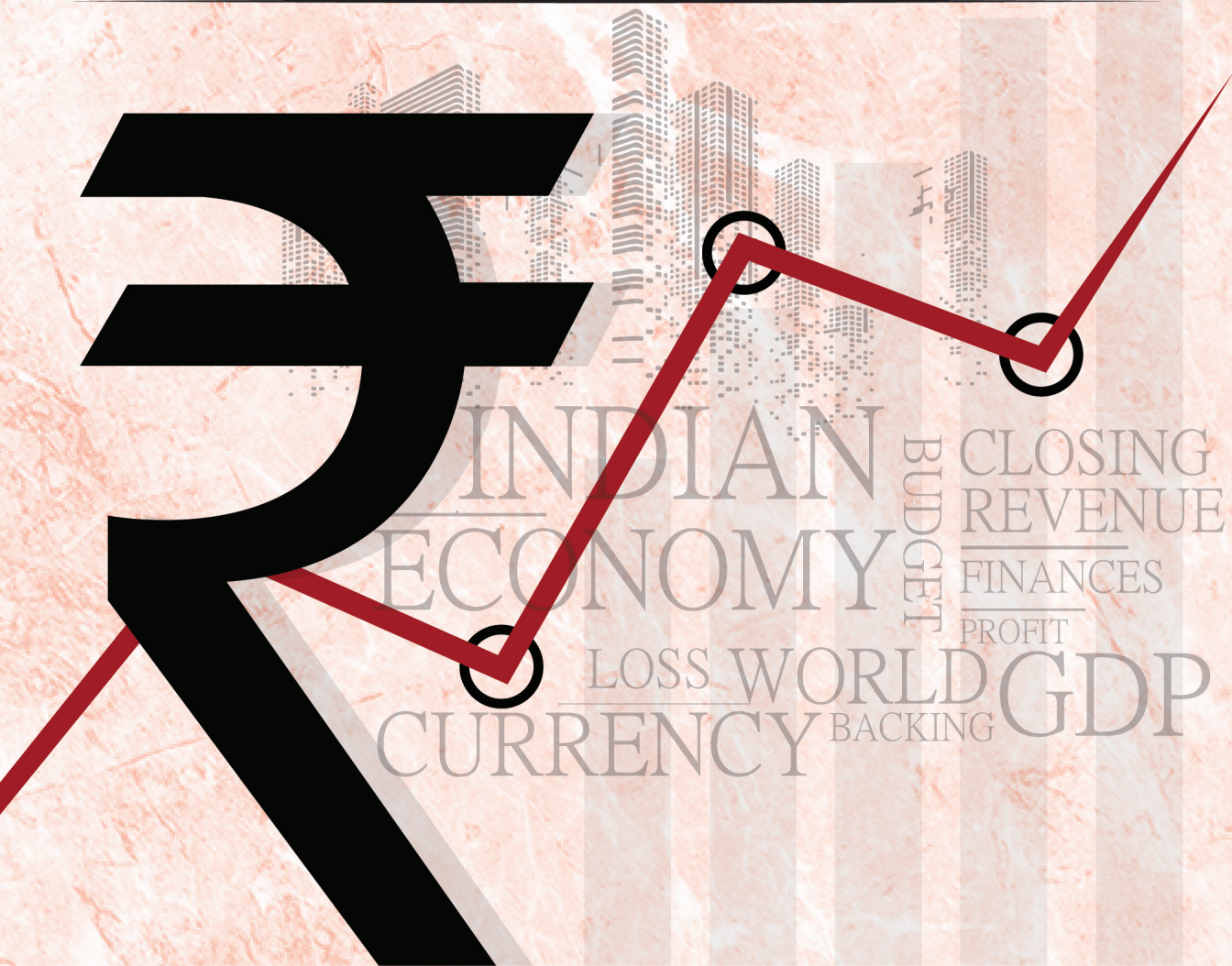


भारत की अर्थव्यवस्था

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी



संपादक की कलम से

प्रिय साथियों,

हमारी पिछली किताबों (भारत का भूगोल, भूगोल तथ्य एवं सिद्धांत, भारत की राजव्यवस्था तथा आधुनिक भारत का इतिहास) को मिली शानदार प्रतिक्रियाओं के लिए हम आपको विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी किताबें लॉन्च होने के बाद से ही यूपीएससी सेगमेंट में अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए बेस्ट सेलर लिस्ट में हैं।

संघ लोकसेवा आयोग के लिए सर्वोत्कृष्ट, हमारी पूर्व की किताबों को मिली भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, हम सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने के अपने मिशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लगा रहे हैं। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन आपको हमारी पुस्तक 'भारत की अर्थव्यवस्था' का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है।

यह पुस्तक उन चिंताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनका सामना छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के दौरान करना पड़ता है। छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं कि क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है, किसी विषय के लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई और आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। इन सबसे ऊपर, समेकित अध्ययन सामग्री की अनुपस्थिति और कई स्रोतों से सूचना हमारे छात्रों की तैयारी में बाधा डालती है।

यह पुस्तक इन समस्याओं से निपटने और छात्रों के ज्ञान के आधार में सुधार करने, उनकी तैयारी के दौरान उनके कीमती समय की बचत करने और उनके सामने आने वाली कई शैक्षणिक गलतफहमियों को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं:

- इस पुस्तक का उद्देश्य यूपीएससी की वर्तमान प्रवृत्तियों और पैटर्न के आधार पर आपकी तैयारी को केंद्रित और प्रासंगिक, पुनरीक्षण-अनुकूल और अप-टू-डेट बनाना है।
- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की आवश्यकताएं इस पुस्तक का विशेष फोकस हैं।
- हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती है कि सामग्री स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली हो, ताकि छात्र अपने लाभ के लिए अवधारणाओं को सीख सकें और याद कर सकें।
- विगत वर्षों के प्रश्न, जहां भी आवश्यक हो, हमने छात्रों को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से जुड़ी सभी मौलिक अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण और तालिकाओं को शामिल किया है।
- पूरी ईमानदारी के साथ आपको, आपकी सिविल सेवा परीक्षा की, स्टडी आईक्यू टीम तैयारी में सर्वश्रेष्ठ होने की कामना करती है, और हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी इस अश्वमेध यात्रा में आपकी सहायता अवश्य करेगी।

विषय सूची विस्तृत

1. अर्थशास्त्र का अर्थ.....	1
1.1 अर्थशास्त्र की चार परिभाषाएँ.....	1
1.2 अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएँ.....	5
1.3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र.....	9
1.4 अर्थशास्त्र का वर्गीकरण.....	10
1.5 उत्पादन के कारक.....	14
1.6 एक अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति की अवधारणा	14
1.7 बाजार संतुलन	19
2. मुद्रा.....	21
2.1 धन का विकास.....	21
2.2 कमोडिटी मनी.....	21
2.3 धातु मानक.....	22
2.4 पूर्णकाय मुद्रा.....	22
2.5 सांकेतिक मुद्रा.....	23
2.6 कागजी मुद्रा मानक.....	23
2.7 कानूनी निविदा.....	23
2.8 बैंक मनी/डिपॉजिट मनी.....	24
2.9 इलेक्ट्रॉनिक आदेश/डिजिटल भुगतान.....	25
2.10 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)	26
2.11 सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा	27
2.12 प्लास्टिक मनी	29
2.13 क्रिप्टो करेंसी.....	30
2.14 मुद्रा के कार्य.....	31
2.15 मुद्रा की आपूर्ति.....	32
2.16 मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक.....	33
2.17 मुद्रा गुणक	34
2.18 कैशलेस इकॉनमी	35

3. मुद्रास्फीति	39
3.1 मुद्रास्फीति के प्रकार	39
3.2 मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)	44
3.3 मुद्रास्फीति की माप (Measures of Inflation).....	49
3.4 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय (Measures to Control Inflation)	54
3.5 मुद्रास्फीति से संबंधित अवधारणाएं/शर्तें (Concepts/terms related to Inflation)	56
4. मौद्रिक नीति.....	63
4.1 विस्तारक मौद्रिक नीति का कार्य	63
4.2 संकुचनकारी मौद्रिक नीति का कार्य करना.....	64
4.3 भारत में मौद्रिक नीति ढांचा	65
4.4 भारत में मौद्रिक नीति ढांचे का विकास.....	66
4.5 मौद्रिक नीति समिति (MPC).....	67
4.6 मात्रात्मक उपकरण.....	68
4.7 रेपो रेट की क्रियाविधि.....	70
4.8 रिवर्स रेपो रेट की क्रियाविधि.....	71
4.9 गुणात्मक उपकरण/साधन	78
4.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल).....	79
4.11 भारत में मौद्रिक नीति के प्रसारण में चुनौतियां	80
5. बैंकिंग	84
5.1 बैंकों के कार्य.....	84
5.2 भारत में बैंकिंग संरचना का इतिहास	85
5.3 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई).....	87
5.4 बैंकों का वर्गीकरण	87
5.5 बैंकिंग विनियमन (BR) (संशोधन) अधिनियम, 2020	96
5.6 विकास बैंक	97
5.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी).....	99
5.8 बैंक की वित्तीय स्थिति को समझना	103
5.9 बेसल मानदंड	105
5.10 बैड लोन	108

5.11 ऋण के प्रकार: ब्याज दर के आधार पर	108
5.12 ऋण के प्रकार: उधारकर्ताओं के आधार पर	109
5.13 टीजर ऋण (Teaser Loans)	110
5.14 गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA)	110
5.15 भारत में एनपीए संकट	112
5.16 बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों हेतु समितियाँ	121
5.17 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय	124
5.18 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण	125
5.19 वित्तीय समावेशन	127
5.20 बैंकिंग में हालिया अद्यतन	130
6. राष्ट्रीय आय	137
6.1 जीडीपी गणना से संबंधित कुछ अवधारणाएँ	141
6.2 जीडीपी के प्रकार	141
6.3 राष्ट्रीय आय की गणना	147
6.4 भारत में जीडीपी की गणना	149
6.5 भारत में राष्ट्रीय खातों में नए परिवर्तन	150
6.6 सकल मूल्य वर्धन (GVA)	152
6.7 जीडीपी और जन कल्याण	153
6.8 विकास को मापने के अन्य उपाय	154
7. संवृद्धि, विकास और योजना	159
7.1 आर्थिक विकास	159
7.2 आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास: एक तुलना	159
7.3 आर्थिक विकास को मापने की जरूरत क्यों	160
7.4 आर्थिक विकास को मापने के लिए सूचकांक	160
7.5 केंद्रीय योजना	165
7.6 भारत में विकेंद्रीकृत योजना	170
7.7 भारत में योजना से जुड़े निकाय	172
7.8 भारत में आर्थिक सुधार	175

8. कराधान.....	183
8.1 करों का वर्गीकरण	183
8.2 भारत में कराधान.....	186
8.3 कराधान से संबंधित अवधारणाएँ	203
8.4 भारत में कर सुधार.....	205
8.5 कर अपवचना और कर परिहार (Tax Evasion and Tax Avoidance)-----	207
9. सार्वजनिक वित्त	211
9.1 बजट.....	211
9.2 बजट घाटा	218
9.3 सार्वजनिक ऋण	221
9.4 ऋण-जीडीपी अनुपात	224
9.5 भारतीय बजट में हालिया बदलाव	225
9.6 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) -----	225
9.7 सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड	225
9.8 राजकोषीय नीति	226
10. वित्तीय बाजार.....	239
10.1 मुद्रा बाजार.....	240
10.2 संगठित मुद्रा बाजार उपकरण.....	241
10.3 पूंजी बाजार	245
10.4 डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (DRs) -----	257
10.5 पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी-नोट्स	258
10.6 निवेश कोष (Investment Fund) -----	258
10.7 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF)-----	259
10.8 हेज फंड (Hedge Funds) -----	259
10.9 रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) -----	260
10.10 वेंचर कैपिटल	261
10.11 स्टॉक एक्सचेंज और सूचकांक	262
10.12 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी).....	263
10.13 कमोडिटी बाजार.....	264

10.14 वित्तीय बाजारों से संबंधित कुछ शब्द	265
11. बाह्य क्षेत्र	268
11.1 भुगतान संतुलन (बीओपी)	268
11.2 भुगतान संतुलन के घटक	269
11.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	271
11.4 विदेशी मुद्राभंडार	273
11.5 भारत के चालू खाता घाटे से संबंधित मुद्दे	273
11.6 भारत में 1991 का भुगतान संतुलन संकट	277
11.7 विदेशी मुद्रा बाजार	278
11.8 विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली: भारत	283
11.9 मुद्रा परिवर्तनीयता	284
11.10 व्यापार समझौते	288
11.11 व्यापार बाधाएं	289
12. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन	292
12.1 कृषि	292
12.2 भारत में कृषि विकास - हरित क्रांति	295
12.3 फसलों के प्रकार	299
12.4 कृषि आदान	300
12.5 भारत में उर्वरक नीति	302
12.6 उर्वरक सब्सिडी	304
12.7 कृषि यंत्रीकरण	309
12.8 कृषि वित्त	310
12.9 कृषि बीमा	315
12.10 कृषि सब्सिडी	316
12.11 कृषि सब्सिडी और विश्व व्यापार संगठन (WTO)	321
12.12 कृषि मूल्य निर्धारण नीतियाँ	322
12.13 कृषि विपणन	330
12.14 अधिप्राप्ति, भंडारण और माल भण्डारण	337
12.15 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	344

12.16	बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडार).....	351
12.17	खाद्य सुरक्षा.....	353
12.18	किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी.....	357
12.19	कृषि निर्यात.....	362
13.	संबद्ध क्षेत्र	369
13.1	पशुधन क्षेत्र	369
13.2	डेयरी उद्योग.....	373
13.3	मुर्गी पालन	375
13.4	देश में पशुधन विकास के लिए सरकारी पहल	378
13.5	मछली पालन	385
13.6	एपीकल्चर/मधुमक्खी पालन	395
13.7	रेशम उत्पादन	400
14.	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र	403
14.1	खाद्य प्रसंस्करण.....	403
14.2	भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र.....	408
14.3	भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई पहल..	413
15.	भूमि सुधार	421
15.1	भूमि सुधार.....	421
15.2	भूदान और ग्रामदान आंदोलन.....	422
15.3	भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का इतिहास.....	423
15.4	जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950.....	424
15.5	काश्तकारी सुधारों से जुड़ी चुनौतियाँ.....	426
15.6	स्वामित्व योजना.....	433
15.7	भूमि संवाद.....	435
15.8	भारत में भूमि सुधारों का मूल्यांकन.....	438
16.	औद्योगिक नीति एवं विनिर्माण.....	441
16.1	भारतीय उद्योग.....	441
16.2	स्वतंत्रता के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्र	441
16.3	भारतीय औद्योगिक नीति.....	442

16.4	भारतीय औद्योगिक नीति का विकास.....	443
16.5	विनिर्माण क्षेत्र.....	450
16.6	उद्योग 4.0.....	462
16.7	उद्योग: वर्गीकरण.....	463
16.8	भारत के आधारभूत उद्योग (Core Industries of India)-----	469
17.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र.....	472
17.1	MSME की परिभाषा.....	472
17.2	भारत में MSME -----	473
17.3	भारत में MSME क्षेत्र के विकास के लिए किए गए सुधार.....	477
17.4	MSME क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी योजनाएं:.....	478
17.5	MSME से संबंधित कुछ पोर्टल.....	481
18.	आधारभूत संरचना.....	484
18.1	आधारभूत संरचना की श्रेणियाँ.....	484
18.2	देश में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियाँ.....	485
18.3	आगे की राह.....	487
18.4	आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित सरकारी उपाय.....	487
18.5	यातायात.....	489
18.6	रसद क्षेत्र.....	507
19.	भारत में सेवा क्षेत्र.....	513
19.1	भारत के सेवा क्षेत्र में प्रमुख उप-क्षेत्र.....	515
19.2	ई-कॉमर्स.....	518
20.	बेरोजगारी.....	523
20.1	बेरोजगारी की अवधारणा.....	523
20.2	बेरोजगारी पर डेटा के स्रोत.....	523
20.3	रोजगार से संबंधित नवीनतम रुझान.....	526
20.4	भारत में बेरोजगारी के प्रकार.....	526
20.5	औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र.....	527
20.6	भारतीय कार्यबल का अनौपचारिकीकरण.....	529
20.7	बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए सरकार की पहल.....	531

20.8	भारत में श्रम सुधार	533
21.	गरीबी और असमानता	544
21.1	गरीबी	544
21.2	असमानता	555
22.	समावेशी विकास	559
22.1	समावेशी विकास के तत्व	559
22.2	समावेशी विकास की आवश्यकता	560
22.3	भारत में असमानता के कारण	561
22.4	समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियां	562
22.5	समावेशी विकास के लिए सुझाव	563
22.6	समावेशी विकास का पैमाना	563
22.7	समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता के बाद से भारत द्वारा किए गए उपाय	566
22.8	भारत द्वारा अर्थव्यवस्था में समावेशी संवृद्धि हासिल न कर पाने के कारण	569
22.9	सतत विकास	569
22.10	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)	573
22.11	समावेशी संवृद्धि के लिए योजनाएँ	573
23.	जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी	576
23.1	जनसंख्या	576
24.	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	591
24.1	महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान	591

प्रतिदर्श पेज

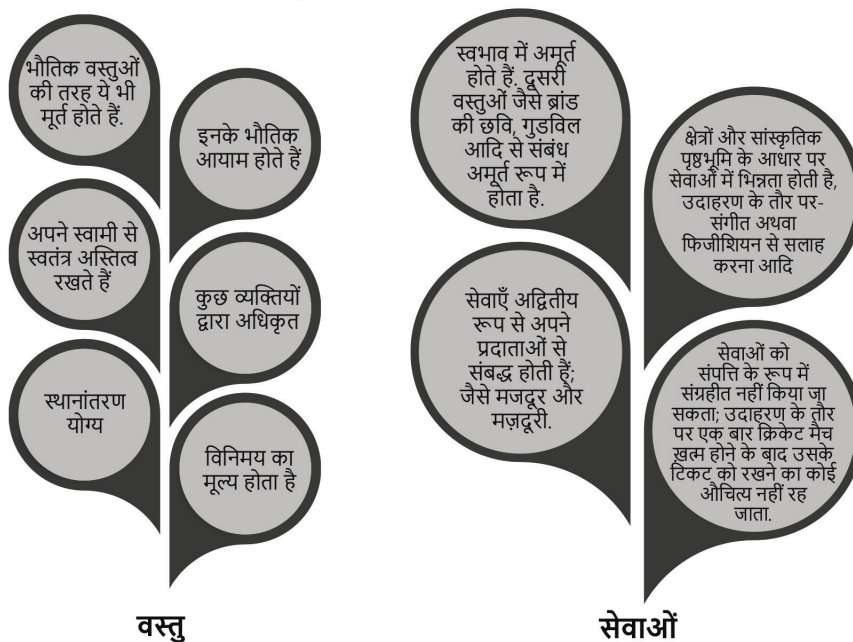
गुण	दोष
यह कृषि और उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं, ग्रामीण और शहरी आदि के बीच संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।	आमतौर पर, सरकारी और निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करने के बजाय अपनी गतिविधियों में प्रतिस्पर्धी होते हैं।
सरकार संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर सकती है क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रूप से और निजी क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका नियंत्रण है।	राष्ट्रीयकरण का डर निजी उद्यमियों को उनके व्यवसाय संचालन और नवीन पहलों में हतोत्साहित करता है।
सरकार न्यूनतम मजदूरी, और राशनिंग, उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना और सामाजिक कल्याण तैयार करके श्रमिकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करती है। पैमाने।	संसाधनों का स्वामित्व, विरासत के नियम और लोगों का लाभ का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच के अंतर को बढ़ाता है।

अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएँ

वस्तुएं और सेवाएँ

एक अर्थव्यवस्था में, वस्तुएँ और सेवाएँ मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जब तक न कहा जाए, अर्थशास्त्र में 'वस्तु' शब्द में 'सेवा' शब्द भी शामिल है।

वस्तु एवं सेवाओं की विशेषताएँ



डिफ्लेशनरी/अवस्फीति गैप (Deflationary Gap)

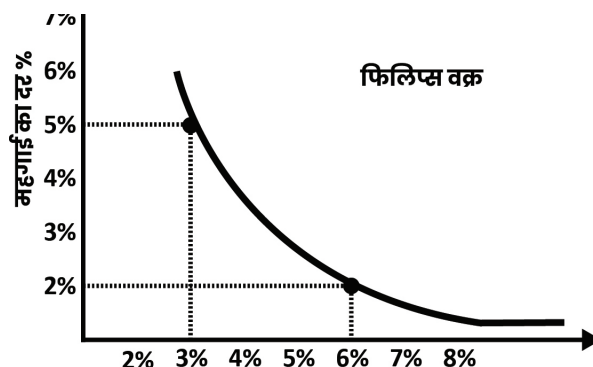
जब संभावित सकल घरेलू उत्पाद अधिक होता है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कम होता है तो इस अंतर को अपस्फीति अंतर कहा जाता है। यह पूर्ण रोजगार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर है। अपस्फीतिकारी अंतराल के लिए वस्तुओं व सेवाओं की घटी हुई मांग होनी चाहिए जो कारकों के कारण उत्पादन को कम करती है जैसे कि व्यापार गतिविधियों में कमी, सरकारी व्यय में कमी, समग्र रोजगार का निम्न स्तर आदि।

उपरोक्त कारक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जहां वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संभावित सकल घरेलू उत्पाद से कम हो जाता है जिससे अपस्फीतिकारी अंतर उत्पन्न होता है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत में और कमी आएगी, इसलिए कीमतों में कमी आएगी, यानी बाजार में अपस्फीति दिखाई देगी।

यह अपस्फीति अंतराल एक अर्थव्यवस्था में संकुचन के बिंदु को इंगित करता है। बाजार में पैसे का प्रवाह कम होने के कारण लोग वस्तुओं व सेवाओं पर कम खर्च करते हैं। बाजार में घटी हुई मांग उत्पादन को और नीचे ले जाती है, लेकिन अगर उत्पादन मांग के अनुसार होता है तो बाजार में संतुलन बनाने के लिए कीमत में और बदलाव होता है। यह एक सस्ते बाजार की ओर ले जाता है, और इसलिए यह गरीब लोगों के लिए अच्छा है।

मुद्रास्फीति सर्पिल (Inflationary spiral)

जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, श्रमिक अपनी आवश्यक जरूरतों व जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए उच्च मजदूरी की मांग करते हैं। फर्मों को अपना वेतन बढ़ाना पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं व सेवाओं की लागत बढ़ जाती है जो आगे चलकर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बनती है। 'मजदूरी और कीमतों' के इस पुण्य चक्र को मुद्रास्फीति सर्पिल या मजदूरी-मूल्य सर्पिल के रूप में जाना जाता है।



फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)

फिलिप्स का वक्र बताता है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी का विपरीत संबंध है। यह विलियम फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी कम होती जाती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच इस व्युत्क्रम संबंध को एक वक्र के रूप में देखा जा सकता है जैसा कि दिखाया गया है:

जैसा कि आप देख सकते हैं, X-अक्ष बेरोजगारी दर दिखाता है, और Y-अक्ष मुद्रास्फीति की दर दिखाता है। जैसे ही X-अक्ष पर मुद्रास्फीति 2% से 5% तक बढ़ती है, Y-अक्ष पर बेरोजगारी की दर 6% से घटकर 3% हो जाती है। इसलिए बिंदु A से बिंदु B पर स्थानांतरण होता है। विलियम फिलिप्स ने यह भी कहा कि बिंदु B, बिंदु A से बेहतर स्थिति है। बिंदु B पर अर्थव्यवस्था बिंदु A से बेहतर है।

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्र. इसके प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? (2013)

- (a) सार्वजनिक ऋण की अदायगी
(b) बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना
(c) बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना
(d) बजट घाटे को वित्त करने के लिए नया पैसा बनाना

उत्तर: (d)

प्र. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? (2015)

- (a) भारत में महंगाई को नियंत्रित करना भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है।
(b) महंगाई को नियंत्रित करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भूमिका नहीं है।
(c) घटी हुई मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है।
(d) धन परिसंचरण बढ़ने से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

उत्तर: (c)

प्र. भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं है? (2019)

- (a) गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना।
(b) भारतीय कर्जदारों को रुपये में मूल्य वर्धित मसाला बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
(c) बाह्य वाणिज्यिक उधारी से संबंधित शर्तों को आसान बनाना।
(d) एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना।

उत्तर: (d)

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसके कारण मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है/बढ़ सकती है? (2021)

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. विस्तारवादी नीतियां | 2. राजकोषीय प्रोत्साहन |
| 3. मुद्रास्फीति-अनुक्रमण मजदूरी | 4. उच्च क्रय शक्ति |
| 5. बढ़ती ब्याज दरें | |

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 3, 4 और 5 (c) केवल 1, 2, 3 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (2020):

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य का भार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से अधिक है।

- **अप्रत्यक्ष करों में**, अधिकांश वस्तुओं को कवर करने और 1996-97 तक एक व्यापक क्रेडिट प्रणाली प्रदान करने हेतु उत्पाद शुल्क के लिए मोडवैट क्रेडिट प्रणाली (MODVAT Credit System) का विस्तार किया गया था। ग्यारह दरों को आपस में विलय करके तीन दरें रखी गयी।
- 2005 में 21 राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट/VAT) पेश किया गया था। मूल्य वर्धित कर ने इनपुट पर भुगतान किए गए करों को क्रेडिट किया और सोपानिक प्रभाव से राहत प्रदान की।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003

राजकोषीय समेकन वांछित परिणाम देने में विफल रहा क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं थी। यही कारण है कि एक मजबूत संस्थागत/सांविधिक तंत्र का समर्थन प्रदान करने के लिए **26 अगस्त, 2003 को राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA)** लाया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिकी स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना है।

FRBM अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

1. FRBM के अनुसार, सरकार को राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% के वार्षिक कमी लक्ष्य के साथ **2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% (मध्यम अवधि) तक कम करना चाहिए।**
2. FRBM अधिनियम राजकोषीय समेकन के लिए एक कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अब केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने, राजस्व घाटे को खत्म करने और बाद के वर्षों में राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने के उपाय करना अनिवार्य है।
3. यह अधिनियम सरकार को राजकोषीय समेकन के मार्ग का पालन करने के लिए बाध्य करता है। सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य असाधारण आधारों, जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है (**एस्केप क्लॉज**) के मामले में राजकोषीय समेकन के रास्ते से हट सकती है।
4. यह अधिनियम सरकार द्वारा आरबीआई से उधार लेने पर रोक लगाता है। इस प्रकार, **मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से स्वतंत्र बनाता है।** इसके अलावा, यह अधिनियम 2006 के बाद आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की खरीद पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे सरकारी घाटे के मौद्रिकरण को रोका जा सके।
5. इस अधिनियम में सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष तीन नीति वक्तव्य रखने की भी आवश्यकता है: **मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और व्यापक आर्थिक ढांचा नीति वक्तव्य/मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट।**
6. राज्य स्तर पर राजकोषीय अनुशासन प्रदान करने के लिए, **बारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (FRLs) शुरू करने के लिए सशर्त ऋण पुनर्गठन और ब्याज दर राहत के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहन दिया। सभी राज्यों ने अपने-अपने FRL लागू किए हैं।**